[Shri M. L. Sondhi]

I regret the Ministry of External Affairs is not always mindful of our close relationship with Czechoslovakia and other countries of Eastern Europe which for them are sometimes the *terra incognite* beyond the Suez Canal; they regard them as *vilayat,* as all shades of England, or something like that. Therefore, what we need is the specific knowledge, the historical knowledge, and a knowledge in which ultimately there is reconciliation of the national aspirations, the national past and a great future of human unity which awaits mankind ahead of us.

17·41 Hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Indian Goods and Equipment Held by Pakistan

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि 1947 से ले कर 1965 तक भारत की नीति पाकिस्तान के साथ जो रही है वह पूरी तरह से नाकामयाब रही है। 1965 में पाकिस्तान ने हमारा 101 करोड़ रु० का सामान पकड़ा और हम ने केवल 27 करोड़ रु० का सामान उन का पकड़ा। मन्त्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब पाकिस्तान ने प्राइज़ कोर्ट इस्टैब्लिश कर के हमारा साढ़े पांच करोड़ रु० का माल जब्त किया और लड़ाई डिक्लेअर कर के कहा कि फार्मल वार में जो हम ने जब्त किया है वह हमारा है, हम ने उस को प्राइज़ में लिया है, और इस के ऊपर हमारे सिक्योरिटी कौंसिल के प्रतिनिधि मि०पार्थसारिथी ने आब्जेक्शन भी किया और कहा कि हम इसके लिए डैमेजेज क्लेम करेंगे, क्या हिन्दुस्तान ने भी उसी तरह से प्राइज़ कोर्ट इस्टैब्लिश कर के यह कहा था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उस को हम फार्मल वार मानते हैं? अगर कहा था तो उन्होंने क्या किया और जो डैमेजेज की बात सिक्योरिटी कौंसिल में कही गई थी उस के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की?

दूसरी चीज यह कि ताशकन्द ऐग्रीमेंट में नौ बातें कही गई हैं। नौ बातों में से केवल एक बात को छोड़ कर, जिस में उन्होंने यह कहा है कि:

> "The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn not later than 25th February, 1966 to the positions they held prior to the 5th August, 1965, and both sides will observe the ceasefire terms and the ceasefire line."

कोई दूसरी बात पाकिस्तान ने नहीं मानी। आज ताशकन्द ऐग्रीमेंट एक डैड लेटर है। पाकिस्तान उस को नहीं मानता। जिस तरह से लड़ाई बगैर दोनों तरफ के लोगों लड़ें नहीं हो सकती उसी तरह से दोस्ती भी जब तक दोनों तरफ से इरादा न हो, नहीं हो सकती। जब यह डेड लेटर है और उस पर पाकिस्तान अमल नहीं कर रहा है, हमारी तरफ से एकतरफा कार्रवाई हो रही है, तब मैं माननीय मन्त्री महोदय से दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जब ताशकन्द ऐग्रीमेंट हुआ तब जब तक पाकिस्तान ने बाकी कंडिशन्स को पूरा नहीं किया, आप हाजी पीर, लाहौर और स्यालकोट से वापस क्यों हट आये? हमारा माल पाकिस्तान ने वापस नहीं किया, और जो दूसरी शर्तें थीं उन को भी उस ने पूरा नहीं किया, लेकिन आप शरीफ आदमी की तरह से वापस हट गए। आप ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि पाकिस्तान शर्तों को मानेगा या नहीं। यह एक बहुत बड़ी फेल्लोर गवर्नमेंट आफ इंडिया की रही है, जिस ने जो चीज उस के हाथ में थी उस को पूरा कर दिया और अब पाकिस्तान उस को नचा रहा है और हम को उन की उंगली पर नाचना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि ताशकन्द ऐग्रीमेंट ऐब्रोगेट किया जाये, उसे खत्म किया जाये। क्योंकि इस तरह का एकतरफा फैसला आगे नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने विधड्राल क्यों किया, जब तक सारी कार्रवाई पूरी नहीं हुई?

तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान सामान बेच रहा है और सामान का इस्तेमाल भी कर रहा है। आप ने उन की चीजें यूनिलेटरली वापस कर दीं। जब पाकिस्तान ने आप का सामान वापस नहीं किया तब आप ने कितना सामान उन का यूनिलेटरली वापस कर दिया और क्यों कर दिया ? क्या आप ने पाकिस्तान के साथ बात चीत की थी ? रशिया से जब आप ने बात चीत की, जिस के लिए आप कहते हैं कि रूस की सरकार ने इस पर कार्रवाई की थी, तब रूस ने आप को क्या जवाब दिया था ?

चौथी चीज यह कि यहां पर हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं लेकिन हिन्दुस्तान में नौकरी या रोजगार करते हैं। जब सरकार के प्रोटेस्ट नोट काम नहीं आ रहा है, रूस के साथ बात चीत करने का कोई लाभ नहीं रहा है तब क्या यह सरकार जो पाकिस्तानी लोग हिन्दुस्तान में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं उन को एकदम पाकिस्तान भेजेगी ?

अब जो बात मैं कह रहा हूं उस को लिख लीजिए क्योंकि मैं इस का जवाब साफ तौर से चाहता हूं ? हम ने जितनी मजबूती से एनिमी ऐक्ट लागू करना चाहा वह नहीं किया जब कि पाकिस्तान ने पूरी मजबूती से उसको लागू किया। अब हम को मालूम करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी नेशनल है उन के शेअर्स कहां कहां हैं और उन को पूरी तरह से रिव्यू कर के दुबारा लागू करना चाहिए।

एक चीज आप ने कही थी कि ब्रिटिश इंश्योरेंस कम्पनी से आप को पैसा मिला क्योंकि कुछ सामान हमारा ब्रिटिश इंश्योरेंस कम्पनीज के साथ था। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां से कितना पैसा मिला ? और क्या सरकार अब आगे पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपनी नीति को रिव्यू करेगी और ट्रेड के बारे में, कामर्स के बारे में पाकिस्तान हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसी तरह की नीति होगी ? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर पिछले हफ्ते सदन में कुछ बहस हुई थी जब हम लोगों ने विदेशी या शत्रुओं के करोड़ों रुपयों के बारे में चर्चा की थी। तब भी एक सुझाव इस सरकार के सामने आया था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए हो या हेग के इंटर-नेशनल कोर्ट के जरिए हो और जो माल मता हमारा पाकिस्तान के पास पड़ा है उस को वापस लाने की बात की जानी चाहिए।

मुझे मन्त्री महोदय से एक बात जो अर्ज करनी है वह यह है कि यह प्रश्न सिर्फ सरकार और सरकार के रिश्ते का नहीं है। हिन्दुस्तान के हजारों ऐसे नागरिक हैं चाहे वह छोटे-मोटे उद्योग वाले हों या मामूली नागरिक हों, जिनका सामान आज पाकिस्तान के हाथ में पड़ा है, और वे भी बहुत लाचार लोग हैं क्योंकि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिस से वहां पड़ा हुआ उन का माल मता वापस हो जाए। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब तक वह पाकिस्तान से यह सारा माल मता हासिल नहीं कर सकती है तब तक कम से कम अपनी पूंजी से उन हिन्दुस्तान के नागरिकों को, जिन की सम्पत्ति वहां पर है, कुछ देने का काम करेगी ?

साथ ही यहां पर पोस्टल इंश्योरेंस चलता है। जिस समय पार्टिशन हुआ था उस के पहले पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम में जो लोग कराची में रहते थे या आज जो पाकिस्तान का इलाका कहलाता है वहां रहते थे, चाहे वह सरकारी कर्मचारी थे या सामान्य नागरिक, उन्होंने पोस्टल इंश्योरेंस पालिसीज ली थी। बटवारे के बाद भी हिन्दुस्तान में उन पालिसियों को आगे चलाने का काम हुआ और हमारी सरकार ने उनके ऊपर लोगों से प्रीमियम लिया। मेरी मालूमात के अनुसार लाखों नहीं करोड़ों रुपयों के प्रीमियम भारत सरकार ने 1947 के ऐसे पालिसी होल्डरों से लिया है जिन्होंने

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

पाकिस्तान बनने के पहले वहां पर पालिसियां ली थीं। अब जो पालिसियां मैच्योर हो गई हैं उन के पैसा देने की जब बात आती है तब सरकार उस को नहीं दे रही है। मैं सरकार से इस बात का भी खुलासा चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को जिन की इंश्योरेंस पालिसीज आज मैच्योर हो गई हैं या जो लोग मर गए हैं और उन के क्लेम्स आए हैं, जब तक पाकिस्तान आप के साथ पूरे सरकारी लेबेल पर कोई समझौता नहीं करता तब तक उन लोगों की अड़चनों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए पैसा देंगे ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : जब से हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ है तब से ही हिन्दुस्तान की नीयत यह रही है कि पाकिस्तान के साथ उसके मैत्री सम्बन्ध कायम रहें। इन मैत्री सम्बन्धों को कायम रखने के लिए गवर्नमेंट ने कई बार ग्रम भी खाया है और रियायतें भी पाकिस्तान को दी हैं। कभी कभी तो उसको ऐसा करते समय नीचा भी देखना पड़ा है। हर सम्भव प्रयत्न किया गया है कि किसी भी कीमत पर उसके साथ हमारे दोस्ती के सम्बन्ध कायम रहें। मैंने प्रेज़ीडेंट अयूब द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ा है जिस का शीर्षक है, फ्रेंडस नाट मास्टर्ज। इसको पढ़ने से यह मालूम हुआ है कि वह हिन्दुस्तान के बारे में यह सोचते हैं कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नम्बर एक है और इसी प्रकार का सलूक हिन्दुस्तान पाकिस्तान से करता आ रहा है, हिन्दुस्तान की नीयत पाकिस्तान के बारे में साफ नहीं है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने का विचार रखता है, उसको हड़पने का विचार रखता है। पाकिस्तान के प्रैजीडेंट के इन विचारों के बावजूद भी हमने कई रियायतें पाकिस्तान को दी हैं और दोस्ती का हाथ ही हमेशा आगे बढ़ाया है। हमने ग्रम भी कई बार खाया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो तजुर्बा भारत सरकार का हुआ है इससे क्या वह अब भी कोई शिक्षा लेने के लिए तैयार है या नहीं है। क्या पाकिस्तान के प्रति जैसे को तैसा वाली नीति बरतने के लिए सरकार अब तैयार है या नहीं है। जिस माल मते को पाकिस्तान ने पिछले युद्ध के बाद पकड़ा था और जिन के माल को पकड़ा था उनको कम्पेंसेट करने के लिए और पाकिस्तान से उस माल को प्राप्त करने के लिए क्या भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है या इस पर उसने कोई विचार किया है ? अगर वह हमारे माल को लौटाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हम किन्हीं दूसरे उपायों पर, किन्हीं दूसरे तरीकों से इस कमी की पूर्ति कर सकेंगे, क्या इस पर भारत सरकार ने विचार किया है और अगर किया है तो किस तरह से यह हो सकेगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। कुछ दिन पहले आधे घन्टे की चर्चा के समय उपाध्यक्ष महोदय ने नियम बताया था कि जो आधे घन्टे की चर्चा को ओपन करता है वह पहले बोले और उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब दें। इसके बाद दूसरे सदस्यों को सवाल करने का और जवाब लेने का मौका दिया जाए।

MR SPEAKER : I do not know who has said that. That is wrong. This is the procedure. If somebody follows a different procedure, it is wrong.

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : गुप्त जी ने पहले भी इस मामले पर काफी वजाहत के साथ यहां बहस की थी और तब मिनिस्टर साहब ने उनके सवालों के जवाब दिए थे। आज उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है सिवाय इसके कि उन्होंने कामर्स मिनिस्ट्री से मुताल्लिका जो सवाल थे उन सवालों के साथ कुछ और सवालों को भी जोड़ दिया है जिन का ताल्लुक दूसरी मिनिस्ट्रीज से है। उन्होंने कहा है कि आगे हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंग और फौजी बचाव

के सिलसिले में हम क्या करेंगे। इन मसलों का ताल्लुक ज्यादा तर डिफेंस मिनिस्ट्री से और फौरन मिनिस्ट्री से है।

माननीय सदस्य को याद होगा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई थी उस वक्त जितनी भी प्रापर्टी या जितनी भी जायदाद हिन्दुस्तानियों की पाकिस्तान में थी उसको पाकिस्तान ने जब्त कर लिया था और जितनी जायदाद पाकिस्तानियों की हिन्दुस्तान में थी उसको हमने जब्त कर लिया था। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों वहां पर ज्यादा प्रापर्टी हिन्दुस्तानियों की थी और यहां पर कम प्रापर्टी पाकिस्तानियों की थी। इसकी सब से बड़ी वजह यह है कि हिन्दुस्तानियों का कारोबार वहां ज्यादा था।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह सवाल नहीं पूछा है। अपने आप ही सवाल बना रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारी तरफ से कोई जंग का एलान नहीं हुआ था। उन्होंने ही किया था। जो कुछ भी तब जायदाद जब्त की गई, पकड़ी गई उसको हमने एनीमी प्रापर्टी करार दिया। उसके बाद ताशकन्द एग्रीमेंट हुआ और वह इन जज़बात के तहत हुआ कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात अच्छे हों। इस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान पर एतबार करके इस बात को तस्लीम किया कि जितने भी आपसी झगड़े हैं उन को बातचीत से तय किया जाए। हमने अपनी सफाई दिखाने के लिए, अपनी सच्चाई दिखाने के लिए बहुत सा पाकिस्तान का जो माल जब्त किया था उसको रिलीज़ किया—

श्री कंवर लाल गुप्त : यही तो बेवकूफी की।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी उसके मुकाबले में कुछ माल दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमने जो पाकिस्तान का माल यहां जब्त किया है और जो 27 करोड़ के करीब का है क्या उसको हम बेच दें? अगर ऐसा किया जाता है तो माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि हमारा भी एक अरब से ज्यादा का माल वहां पड़ा हुआ है और वे भी उस माल के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इस वक्त अपना हाथ रोका हुआ है तो महज़ इसलिए कि हमने एक मिसाल कायम की है। अगर हम उनकी प्रापर्टी का तहफ्फुज़ करेंगे तो उन पर भी यह इखलाकी फर्ज आयद हो जाता है कि हमारे हिन्दुस्तानियों की जो प्रापर्टीज़ पाकिस्तान में पड़ी है उसका भी वे तहफ्फुज़ करें। अगर हम इस किस्म की कोई बात करें कि उनकी प्रापर्टी को बेच दें तो क्या माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि वे भी एक अरब से ऊपर की जो जायदाद वहां पर हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों की पाकिस्तान में पड़ी है, उसको बेच दें?

दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि ताशकन्द एग्रीमेंट के बाद हम हाजीपीर से तथा दूसरी जगहों से क्यों हटे। क्यों हम वहां से हटे, यह अब तारीख का एक हिस्सा है। उस में मुझे जाने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने ताशकन्द एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है और हमें भी इसको खत्म कर देना चाहिए। जहां तक हमारी नीति का ताल्लुक है ताशकन्द एग्रीमेंट के हर एक लफ्ज़ पर हम पूरी तरह से पाबन्द रहेंगे, कारबन्द रहेंगे। दुनिया खुद इस बात का फैसला करेगी कि ताशकन्द एग्रीमेंट के जज़बात को कौन ठुकरा रहा है।

जो लोग पाकिस्तान के यहां पर काम करते हैं या जिन की यहां पर जायदाद है उनके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि ज्यों ही पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ हमने फौरन पाकिस्तानियों की जितनी भी यहां जायदाद थी उसको जब्त किया और जो फर्म्ज़ एजेंसियां थीं या शेयर्ज़ थे या सिक्योरिटीज़

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

थी सब को ज़ब्त किया और वे सब इस वक्त बाकायदा हमारे कस्टोडियन के पास मौजूद हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : बेकार का जवाब दिया जा रहा है । मैंने जो सवाल ही नहीं किया उसका जवाब दिया जा रहा है । मैंने पूछा है कि पाकिस्तानी जो यहां पर मुलाजिमत में हैं अभी भी क्या उनको आप वापिस भेजेंगे ?

दूसरी मैंने प्राइज़ कोर्ट की बात कही थी । पाकिस्तान ने प्राइज़ कोर्ट को सैट अप किया । सिक्योरिटी काउंसिल में श्री पारथसार्थी ने कहा है कि हम डैमेजिज़ क्लेम करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि डैमेजिज़ कितने क्लेम किए गए हैं और उसका क्या हुआ है ?

तीसरी बात मैंने रशिया के बारे में कही है । आप बार-बार कह रहे हैं कि रूस को हमने यह कहा, वह कहा । मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या जवाब था ।

ये मेरे तीन सवाल थे। बेकार की कहानी न बताते चले जायें आप ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य को ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए । वह समझते हैं कि वही एक मैम्बर हैं जिन्होंने सवाल किए हैं । एक बिल्कुल उन्होंने मौनोपोली कर रखी है, यह वह समझते हैं । और मैम्बरों ने भी सवाल पूछे हैं और उनका भी जवाब देना है । इंटरनेशनल कोर्ट पर भी मैं आता हूं, प्राइज़ कोर्ट पर भी आता हूं । धीरज रखिए ।

कोई किसी किस्म की हमने प्राइज़ कोर्ट कायम नहीं की है । जितनी जायदाद थी उस सब को हमने एनीमी प्रापर्टी एक्ट के तहत जब्त किया । हमारा इरादा नहीं है कि हम प्राइज़ कोर्ट कायम करें । जहां तक इंटर-नेशनल कोर्ट में इसको ले जाने का ताल्लुक है, अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा ख्याल नहीं है ।

जहां तक कम्पेंसेशन की बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान कम्पेंसेशन वगैरह दे मामला अभी तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है । उस पर कोई खास फैसला नहीं हुआ है । मामला गाहे-ब-गाहे रूस के साथ उठाया जाता है । उस से क्या बात हमारी होती है । जहां तक इसका ताल्लुक है, बात तो वही होती है जो माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं । लेकिन अगर वह जानबूझ कर इसको समझने की कोशिश न करें, तो इस में मेरा क्या कसूर है । रूस के साथ जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि ताशकन्द एग्रीमेंट की शर्तों को हम तो अच्छी तरह से निभा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं आ रहा है, पाकिस्तान उसकी कद्र नहीं कर रहा है, उसको पूरा नहीं कर रहा है । उनके दिमाग में, उनके जहन में यह बात लाई जाती है कि जहां तक ताशकन्द एग्रीमेंट का ताल्लुक है उसकी स्पिरिट को हम मानते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है । हम तो दस कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं लेकिन पाकिस्तान एक कदम भी आगे चलने की कोशिश नहीं करता है—

श्री कंवर लाल गुप्त : रूस वाले क्या सोचते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रूस वाले उसके मुताल्लिक क्या सोचते हैं, पाकिस्तान से वे क्या बात करते हैं या करेंगे, इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूं । लेकिन जहां तक हमारी बात का ताल्लुक है, इसको वे अच्छी तरह से समझते हैं । मैं कैसे कह सकता हूं कि रूस पाकिस्तान को क्या मश्विरा देगा ।

श्री फरनेंडीज़ ने कहा है कि जो माल हमारे पास यहां पड़ा हुआ है या जो हमारे पास पहले सर्टिफिकेट वगैरह पड़े थे, पोस्टल सर्टिफिकेट वगैरह उन से हम लोगों को कम्पेंसेट करें । इस में दो चीज़ों का खयाल रखना चाहिए । एक तो यह है कि तक्सीम के वक्त जो जायदाद यहां रह गई उसको तो इवैक्वी प्रापर्टी करार

दिया गया और जंग के दौरान जो प्रापर्टी हमारे कब्जे में आई वह एनीमी प्रापर्टी है। दोनों जो जायदादें हैं वे अलग-अलग हैं, अलग अलग मदों में आती हैं। एक कस्टोडियन इवैक्वी प्रापर्टी के पास है और दूसरी कस्टोडियन एनीमी प्रापर्टी के पास।

जहां तक इवैकुई प्रापर्टी का ताल्लुक है, उस के लिए अलाहिदा नियम और कानून हैं। जहां तक एनिमी प्रापर्टी का ताल्लुक है, हुकूमत का ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि वह जायदाद बेच कर उन लोगों को कम्पेन्सेट किया जाए, जिन की जायदाद पाकिस्तान में रह गई है।

18 HRS.

श्री जार्ज फरनेन्डीज़: अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह नहीं था कि उस जायदाद को बेच कर यहां के लोगों के नुक्सान को पूरा किया जाये। मैंने यह कहा था कि जब तक सरकारी लैवल पर फ़ैसला नहीं होता है, तब तक सरकार उन लोगों को अपनी तिजौरी से पैसा दे, जो अपना पैसा वहां फंसे होने की वजह से परेशान हैं और जब दोनों सरकारों का आपस में कोई सौदा हो जाए, तो सरकार पाकिस्तान से वह पैसा वसूल करे। आखिर इस सरकार का अपने नागरिकों के प्रति भी कोई कर्त्तव्य है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: माननीय सदस्य हमारी मुश्किल को जानते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बातचीत कर के किसी फ़ैसले पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): He is making a suggestion.

M.R. SPEAKER: The hon. Member is making a suggestion.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: It is again the question of dislocating the whole system of holding the enemy property under the law. We are holding this property on behalf of the enemies and Pakistan is also holding the similar property there. Under the law, till the final settlement....

MR. SPEAKER: You say it cannot be done, if that is so.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: It cannot be done.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Can you make him understand ? You can help us.

There must be some agency to make him understand.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I refuse to understand from the agency which makes the hon. Member understand.

Like the mover of the discussion who has been just going quite wide of the mark as he has been talking about Haji Pir, Chhamb-Jaurian and Lahore sector and about Pakistan goods and the Tashkent Agreement, the hon. Member, Shri Goel, has been telling about Ayub Khan's book, quoting the speeches that India is No. 1 enemy of Pakistan. How am I concerned with that?

अयूबखां की कहीं तकरीर हुई। उन्होंने किताब लिखी। उस का जवाब मैं दूं? हम पाकिस्तान की असलियत को समझते हैं। हम उस के खयालात को अच्छी तरह समझते हैं। हम चौकन्ने हैं और हम किसी से मार खाने वाले नहीं हैं। लेकिन हम गोयल साहब की तरह महज़ कोई किताब पढ़ कर परेशान नहीं होंगे। हुकूमत ने इस किस्म की कई किताबें देखी हैं। जब कभी मुल्क के लिए कोई खतरा पैदा होगा, तो हम डट कर उस का मुकाबला करेंगे; हम किताबों से डरेंगे नहीं।

MR. SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet again at 11 A.M. on Monday, the 19th August, 1968.

18·03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 19, 1968/ Sravana 28, 1890 (Saka)

M39LSS/68—GIPF.